



- दशहरा का पर्व आज मनाया जा रहा है—उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कामना की कि यह त्यौहार द्वीपवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आए।
- पर्यावरण और वन विभाग की ओर से समुद्र और तटों की साफ—सफाई के लिए मिशन एक लाख निर्धारित किया गया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर—बैंकिंग कंपनियों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है।
- समाज कल्याण निदेशालय में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- नगरपालिका परिषद और अंडमान लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण परियोजनाओं में प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है।



पूरे देश के साथ द्वीपसमूह में भी दुर्गा पूजा और दशहरा का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उप राज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने द्वीपवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उप राज्यपाल ने कहा कि यह अवसर हमें अपने जीवन की बुराइयों को नष्ट कर सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कामना की कि यह त्यौहार द्वीपवासियों के जीवन में खुशियां लेकर आए और यह द्वीपसमूह शांति और समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ता रहे।

पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विशाल जौली ने भी दशहरा के अवसर पर सभी द्वीपवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं।



पर्यावरण और वन विभाग की ओर से समुद्र और तटों की साफ—सफाई के लिए मिशन एक लाख निर्धारित किया गया है। विभाग के वन्य प्राणी संभाग के उप—वन संरक्षक संदीप बेहरा ने

आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में बताया कि इसके तहत अगले बारह महीनों के दौरान एक सौ तटों की सफाई की जाएगी और एक लाख किलोग्राम प्लास्टिक एकत्र किए जाएंगे।



राष्ट्रीय खनिज नीति में अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके तहत खनिज संसाधनों के निष्कर्षण में सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, गति और दक्षता के महत्व को पहचानते हुए धातुओं का अनुसंधान के क्षेत्र में उपयोग किया जा रहा है। भारत सरकार का खान मंत्रालय एस एंड टी कार्यक्रम के तहत विभिन्न क्षेत्रों में शोध संस्थानों को अनुदान सहायता प्रदान कर रहा है। मंत्रालय खनिज प्रसंस्करण और रिसाइक्लिंग में स्टार्टअप और एम एस एम ई में अनुसंधान को बढ़ावा दे रहा है, ताकि खनिज क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को अनुसंधान और नवाचार के लिए धन मुहैया कराया जा सके। मंत्रालय ने एस एंड टी-प्रिज्म के तहत खनन, खनिज प्रसंस्करण और पुनर्चकण क्षेत्र में शामिल होने और परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए द्वीपसमूह में भी स्टार्टअप, एम एस एम ई और व्यक्तिगत लोगों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। अधिक जानकारी मंत्रालय के सत्यभामा पोर्टल पर उपलब्ध है।



भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर-बैंकिंग कंपनियों सहित सभी भुगतान सेवा प्रदाताओं को डिजिटल भुगतान सेवा में दिव्यांगजनों की सुविधा का ध्यान रखने का निर्देश दिया है। बैंक ने भुगतान सेवा प्रदाता डिजिटल भुगतान प्रणाली में दिव्यांग अनुकूल आवश्यक बदलाव करने को कहा है। आरबीआई ने कहा कि इस समीक्षा के आधार पर इन प्रणालियों तथा 'पॉइंट-ऑफ-सेल' मशीन जैसे उपकरणों में आवश्यक बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे दिव्यांग लोग इसका आसानी से इस्तेमाल कर सकें।



समाज कल्याण निदेशालय में हाल ही में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के दुष्प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में समाज कल्याण निदेशालय के निदेशक डॉ. नितिन शाक्य ने युवाओं में बढ़ती नशीली दवाओं से संबंधित समस्याओं से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं का सेवन हमारे समाज के लिए एक खतरा है; यह जीवन को नष्ट कर परिवारों को तबाह कर देता है तथा समुदायों को कमजोर करता है।

एनएपीडीडीआर की परियोजना सहायक अन्वम्मा के नेतृत्व में सत्र आयोजित हुआ। उन्होंने मादक द्रव्यों के सेवन के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने 'नशा मुक्त भारत अभियान' के माध्यम से भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जिसका उद्देश्य जागरूकता फैलाना, लत को रोकना और सुधार का समर्थन करना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना, लोगों को शिक्षित करना और ज़रूरतमंदों को सहायता प्रदान करना था।



श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद और अंडमान लोक निर्माण विभाग ने सतत विकास और बेहतर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़क निर्माण परियोजनाओं में प्लास्टिक कचरे के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। मुख्य सचिव केशव चंद्र के निर्देशों के तहत अंतर-विभागीय समन्वय के माध्यम से इस पहल का सफल कार्यान्वयन किया जा रहा है। हाल ही में ब्रुक्शाबाद के मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के दौरे के दौरान, दोनों विभागों ने सड़क निर्माण के कार्य में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की संभावना का पता लगाया। यह संयुक्त प्रयास न केवल प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करेगा, बल्कि द्वीपों की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। यह परिवर्तन प्रक्रिया प्लास्टिक को एक मूल्यवान संसाधन में बदल देती है जिससे सड़कें अधिक टिकाऊ बनेंगी। इससे प्लास्टिक कचरे की मात्रा को कम किया जा सकता है। परिषद ने द्वीपों में पर्यावरणीय लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए अंडमान लोक निर्माण विभाग की अतिरिक्त सड़क निर्माण परियोजनाओं में प्लास्टिक के उपयोग का विस्तार करने की योजना बनाई है। परिषद के सचिव अमित काले ने सड़क कार्यों में प्लास्टिक के पुनः उपयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इससे न केवल प्लास्टिक कचरा कम होता है, बल्कि सड़कें मजबूत भी होती हैं, जो प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल समाधान प्रदान करता है।



डिगलीपुर शैक्षिक अंचल के शिक्षकों के लिए हाल ही में पहल प्लस पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिक्षा सदन के सहयोग से डिगलीपुर के उप-शिक्षा अधिकारी के कार्यालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम का उद्देश्य पहल प्लस पोर्टल के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना था। पहल प्लस छात्रों के सीखने के परिणामों तक पहुंचने और

निगरानी करने के लिए विशेष उपकरण डिजाइन करने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। इस अवसर पर क्षेत्र की उप-शिक्षा अधिकारी सुलोचना मुख्य अतिथि थी। उन्होंने अपने संबोधन में शिक्षकों से हेल्प डेस्क के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपना सहयोग देने का आग्रह किया। कार्यक्रम में मौजूद स्रोत विशेषज्ञों ने छात्रों के प्रदर्शन की निरंतर निगरानी, मूल्यांकन, समय पर और जरूरत के अनुसार सुधारात्मक हस्तक्षेप, शिक्षकों और अभिभावकों की भागीदारी तथा प्रगति मूल्यांकन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम में एक सौ चालीस से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

